10.	केरल, गोवा व तटीय कर्नाटक (A)	805.62	931.75	1127.98
		792.58		
11.	मध्य प्रदेश	812.70	981.36	1112.02
12.	महाराष्ट्र (दक्षिणी)	804.75	847.68	976.52
13.	महाराष्ट्र (उत्तरी)	801.51	873.27	983.60
14.	महाराष्ट्र (मध्य)	763.60	824.24	958.33
15.	पंजाब	773.90	871.04	1084.04
16.	राजस्थान	903.16	915.39	1110.45
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	782.46	937.38	1049.04
18.	उत्तर प्रदेश	795.62	881.03	994.05
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	846.30	938.50	1038.74
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	796.80	898.62	981.81

*उत्तरी और दक्षिणी बिहार के जोनों के मूल्य क्रय-कर आदि के संबंध में न्यायालय के अन्तिम आदेशों की शर्त के अध्यधीन है। यदि बिहार के उपर्युक्त जोनों में फैक्ट्रीयों से कोई राशि वसूल की जानी है तो इसे संबंधित चीनी फैक्ट्री द्वारा चीनी मूल्य समीकरण निधि में जमा कराना होगा।

Plan to increase godown capacity of FCI in Andhra Pradesh

1543. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have any plans to increase godown capacity of FCI in Andhra Pradesh;

(b) if so, details of such plans;

(c) whether it is a fact that FCI has not planned its storage needs properly; and

(d) the steps proposed to improve FCI operations?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMERS AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पंजाब को गेहूं, चावल और चीनी का आवंटन

1544. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पंजाब के वितरण हेतु 31 जनवरी, 1997 तक गेहूं, चावल और चीनी की कितनी मात्रा आवंटित की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के लिए यह आवंटन राज्य सरकार द्वारा की गई मांग के अनुसार किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो गेहूं, चावल और चीनी के कम आवंटन के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या आवश्यक कदम उठा रही है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पंजाब के मामले में जनवरी, 1997 मास के लिए

चावल और गेहूं की मांग, इनके आवंटन और उठान निम्नानुसार है:—

जिन्स	मांग	आवंटन	उठान
चावल	1500 टन	1500 टन	नगण्य
गेहूं	17000 टन	12000 टन	6200 टन

जनवरी, 1996 से प्रभावी पंजाब का लेवी चीनी का मासिक कोटा 8619 टन बैठता है जिसे दिसम्बर, 96, जनवरी, 97 और फरवरी, 97 के लिए 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था जैसाकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के आवंटन अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग, उनकी सापेक्ष आवश्यकताओं, उठान की प्रवृत्ति, केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति, मौसमी उपलब्धता आदि को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। ये आवंटन अनुपूरक होते हैं और ये किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समस्त मांग को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं।

पंजाब सहित अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आवंटन 1.1.96 से 1991 की जनगणना के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता सुनिश्चित करने के एक-समान मानदण्ड के आधार पर किए जा रहे हैं और ये उनकी मांग के आधार पर नहीं किए जाते हैं।

एफ०सी०आई० की आर्थिक लागत

1545. **श्री राम जेठमलानी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक-लागत में विगत वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान गेहूं और चावल की आर्थिक-लागत की अनुमानित राशि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 1996-97 में आर्थिक-लागत का पूर्वानुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) 1993-94 से 1996-97 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा हैंडल किए गए गेहूं और चावल की इकानमिक लागत निम्नानुसार है:—

(रुपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	इकानामिक लागत गेहूं	चावल
1993-94	532.03	665.10
1994-95	551.17	694.71
1995-96 (संशोधित अनुमान)	563.57	746.72
1996-97 (संभावित)	650.00	811.00

देश में औद्योगिक जिले

1546. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में राज्य-वार विशेषकर गुजरात राज्य में औद्योगिक जिलों की संख्या कितनी-कितनी हो जायेगी;

(ख) उन जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) "उद्योग रहित जिला" योजना, 1983 के तहत, जिला उद्योग केन्द्र (डी आई सी) कार्य योजना, 1979-80 के अनुसार देश में कुल 93 जिलों की "उद्योग रहित जिलों" के रूप में पहचान की गई थी। गुजरात में डांगरा जिले की पहचान ऐसे जिले के रूप में की गई थी जिसे "उद्योग रहित जिले" की सूची में शामिल किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व 9 एन आई डी केन्द्रों को पूरा किया गया था तथा 2 एन आई डी केन्द्रों को भारत सरकार द्वारा जून, 1988 में प्रारंभ की गई नई विकास केन्द्र योजना के तहत विकास केन्द्रों में बदल दिया गया था ताकि एन आई डी योजना, जो बन्द कर दी गई थी, को बदला जा सके।

(ग) और (घ) विकास केन्द्र योजना के तहत देश-